अध्यक्ष महोदय : सिंह साहब ने अभीस इ मंत्रालय का चार्ज लिया है । वह इस मसले को स्टडी करवा लेंगे । मुनासिब यह होगा कि वह एडवाइज़री बोर्ड और सी. सी आई. के वर्किन्ग को स्टडी करें और फिर हम इस पर डिसकशन करेंगे ।

अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात

+

*732. **श्री जगपाल सिंह** :

श्री शिव शरण वर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यवान विदेशी मुद्रा में वृद्धि करने के लिए अतिरिक्त खाद्यान्नों का निर्यात जारी रखा जा रहा है यदि हां, तो निर्यात के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न की मात्रा किस आधार पर निर्धारित की गई है ; और

(ख) क्या निर्यात प्रयोजन के लिए खाद्यान्नों की मात्रा निर्धारित करते समय ऐसे निर्यात से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर विचार किया गया था और इस संबंध में पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : (a) Yes, Sir. Export of foodgrains is permitted only after determining the quantities available and the quantity required for domestic consumption.

(b Adequate care is taken to ensure that foodgrains are exported only in such quantities as would not have any adverse effect on the public distribution system. As such, the quantities of non-basmati Rice, Maize and Barley were permitted only within a limited ceiling in the last 3 years and export of wheat is banned.

श्री जगपाल सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी का जो जवाब है और जिस समस्या पर मेरा सवाल है वह इस देश की एक ज्वलन्त समस्या है ।

अध्यक्ष महोदय : कई दफा इसका जवाब आ चुका है । मेरे खयाल में यह सवाल आना ही नहीं चाहिए था । दो दफा इसका जवाब आ चुका है और तीन चार दफा डिक्शन हो चुका है । इसमें कोई नयी बात है नहीं ।

श्री जगपाल सिंह : माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, मैं जानना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में···।

अध्यक्ष महोदय : कई दफा यह बात आ गई है ।

श्री जगपाल सिंह : फिर सवाल क्यों आना ?

अध्यक्ष महोदय : गलती से हो गया ।

श्री जगपाल सिंह : जवाब में भी मजाक किया है और वैसे भी मजाक होता है । एक तरफ तो मन्त्री महोदय सदन में कहते हैं कि पिछले तीन वर्षों से अनाज का निर्यात कर रहे हैं लेकिन आप जानते ही हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 37 करोड़ लोगों को दो समय भरपेट खाना नसीब नहीं हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री जगपाल सिंह : आप उनको जवाब देने से रोकते हैं । उन्होंने जवाब दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि जब पिछले तीन वर्षों में 600-700 करोड़ का गेहूं आयात किया गया फिर इस सदन में कह रहे हैं कि हम गल्ला निर्यात कर रहे हैं, तो 1981, 1982 और 1983 में कितने करोड़ का अनाज आयात किया गया और हाल में कितने करोड़ का और आयात करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कई दफा रिकार्ड पर यह बात आ चुकी है ।

It has already been done on the floor of the House. There is nothing to be said. It is the same thing : old wine in the new bottle.

श्री जगपाल सिंह : लेकिन मन्त्री जी का जो जवाब आया है उस पर मैं कसे चुप बैठ जाऊं ? उन्होंने हाउस को मिसलीड किया है ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी मिसलीड नहीं किया है ।

श्री जगपाल सिंह : गलत जवाब दे रहे हैं कि अनाज निर्यात किया जा रहा है ।

(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब पहले दिया जा चुका है ।

श्री जगपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में गल्ला आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा लगाई गई है और इसी अवधि में खाद्यान्न के निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई है ?

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : मैं माननीय सदस्य को पूरा जवाब दे देना चाहती हूं । चावल, मक्का और बारले के लिए हमारा एक्सपोर्ट पर्मिटेड है । मैं नान-वासमती राइस के सम्बन्ध में पिछले तीन सालों की फीगर्स दे रही हूं । 1980-81 में 142.47 करोड़, 1981-82 164.29 करोड़ और 1982-83 में 128.56 करोड़ का निर्यात किया गया ।

जहां तक वासमती राइस का सवाल है, 1980-81 में 75.45 करोड़, 1981-82 में 174.79 करोड़ और 1982-83 में 110 करोड़ का निर्यात किया गया । हमारी प्रौडक्शन की फीगर्स 1980-81 में 53.63 मिलियन टन और 1981-82 में 53.59 मिलियन टन रहीं । The export of rice has been nearly 10% of our total production, which is negligible.

जहां तक मैज और बारले का सवाल है, हमने कोई निर्यात नहीं किया है हालांकि उसकी पर्मीशन है और व्हीट का निर्यात टोटली बैन्ड है ।

श्री जगपाल सिंह : देश के लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार 600-700 करोड़ का गेहूं आयात कर चुकी है । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस स्थिति को देखते हुए सरकार अगले वर्षों के लिए खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जा रही है या नहीं ?

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : While considering the question of the export of foodgrains, various factors such as production, internal availability price,trend crop prospects, stock position and the requirement of the public distribution system, etc. are taken into account. Export is allowed only of such quantities as are not likely to endanger the public distribution system in our countty or unduly push up prices in the intern market.

(*Interruptions*)

श्री जगपालसिंह : इसके मायने हैं कि देश की गरीब जनता·····

(व्यवधान)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I object to it. You are not giving rice to West Bengal and Tripura, and you are exporting rice.

अध्यक्ष महोदय : क्या पढ़े-लिखे आदमी भी ऐसी बात करते हैं ?

(व्यवधान)

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : This concerns rice and food. This is very important. She has told that is does not affect tkc public distribution system. On the other hand, you say that

because of non-availability of rice, you cannot give it. What is the policy of the government ?

MR. SPEAKER : You know it perfectly well what is the policy.

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY : I want to bring it to the notice of the government.

(Interruptions)

श्री शिवशरण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने कहा है कि निर्यात से देश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । मैं देख रहा हूं कि देश के कोने-कोने में करोड़ों लोग भूख से मर रहे हैं । यह सरकार देश की जनता को धोखा दे रही है । हम यह जानना चाहेंगे कि क्या देश की स्थिति को देखते हुए यह सरकार निर्यात पर रोक लगाएगी या नहीं लगाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब आ गया है ।

Setting up of Bank by Government of West Bengal

*733. SHRI AJIT BAG :

PROF. RUP CHAND PAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) Whether the Reserve Bank of India is delaying the approval of setting up of a Bank by the State Government of West Bengal for a long time ;

(b) If so, whether Government intend to instruct the RBI authorities not to delay the approval any further as it is hampering the State's progress; and

(c) if not, the reasons for the same ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHANA POOJARY) : (a) to (c) According to Reserve Bank of India, the request made by the State Government of West Bengal for issue of a licence to float a company for the purpose of carrying on banking business is under their detailed examination. A final decision in the matter is possible only after this examination is completed.

SHRI AJIT BAG : The request for establishing its own bank under the Banking Regulations Act was made by the Government of West Bengal as far back as January 28, 1981. But still it is under their detailed examination. We do not know how long it will take them to take a decision since already more than two years have passed. However, I would like to know from the hon. Minister whether any other State in India has been allowed to run such a bank; and whether any other State Government request to establish a bank of their own has been pending with the Reserve Bank of India.

SHRI JANARDHANA POOJARY : No other State Government has applied for setting up a new Bank. The hon. Member was pleased to say that the Reserve Bank has taken two years. It is not a simple issue before the nation. If all the States come to the Reserve Bank of Indian asking for more number of banks, it will be vety difficult to give more licences. In the course of 30 years, so far the Reserve Bank has given licences only to two banking companies. One was in 1971, that is for Purbanchal Bank Ltd., which was set up to take over the business of Gauhati Bank Ltd, another was set up in 1973, i.e, Bharat overseas Bank in order to take over perations of the Indian Overseas Bank in Thailand etc. The Reserve Bank of India is a competent authority and it is also a statutory body. The Reserve Bank of India is an objective body and is functioning in an objective way. A decision will be taken after taking into consideration all the aspects.

SHRI AJIT BAG : The private banks are allowed to function under conditions laid down by the Reserve Bank of India. So, I would like to know from the hon. Minister what stands in the way of their allowing a State to run its own bank when private banks are allowed to function and whether the hon. Minister will use his good offices to expedite the process of according sanction by the R.B.I.